



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2012/फाल्गुन 5, 1933

No. 58]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2012/PHALGUNA 5, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2012

जांच शुरुआत (निर्णायक समीक्षा)

**विषय :** चीन जन. गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैट बेस स्टील व्हील्स के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत ।

फा. सं. 15/22/2011-डीजीएडी.—वर्ष 1995 एवं तत्पश्चात् यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "वाणिज्यिक वाहनों के ट्यूब टायर अनुप्रयोग में प्रयुक्त 16" नॉमिनल व्यास से 20" नॉमिनल व्यास वाले फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की संस्तुति की थी ।

(1) यतः सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित मूल जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21 मई, 2006 को जारी अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी द्वारा की गई थी । प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच परिणाम दिनांक 12 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. 57/2007-सीमा-शुल्क द्वारा लगाया गया था । प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी दिनांक 28 नवम्बर, 2007 द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें निश्चयात्मक शुल्क लगाने की संस्तुति की गई थी । अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर राजस्व विभाग ने सम्बद्ध देश के मूल का अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. 124/2007-सीमा-शुल्क द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2007 से लगाया था ।

2) यतः कुष्ठेक हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी के अंतिम जाँच परिणाम के विरुद्ध सीस्टेट के समक्ष अपील दायर की थीं। माननीय सीस्टेट ने अपीलकर्ताओं को निर्णयोत्तर सुनवाई का अवसर प्रदान करने एवं जाँच परिणाम में ऐसी निर्णयोत्तर सुनवाई के परिणामस्वरूप यथावश्यक संशोधन करने हेतु यह मामला अपने दिनांक 11 अगस्त, 2011 के आदेश द्वारा प्राधिकारी के पास वापस भिजवाया था।

3) यतः माननीय सीस्टेट के आदेशों के अनुपालन में और कानून एवं सिद्धान्त संबंधी मामलों पर आदेशों को चुनौती देने के निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों हेतु एक निर्णयोत्तर मौखिक सुनवाई का आयोजन दिनांक 13 दिसम्बर 2011 को किया था और दिनांक 28 नवम्बर 2007 को पहले से जारी अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी और उसमें की गई संस्तुतियों की पुनः पुष्टि करते हुए निर्णयोत्तर जाँच परिणाम दिनांक 10 फरवरी 2012 की अधिसूचना सं. 14/8/2005 - डीजीएडी द्वारा जारी किए थे।

4) यतः मेसर्स कल्याणी लेमरेज लिमिटेड, पुणे और मेसर्स व्हील्स इण्डिया लिमिटेड, चेन्नै ने चीन जन गण. के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का आरोप लगाते हुए उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुसरण में भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की ओर से विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए एक आवेदन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है और सम्बद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा करने, उन्हें जारी रखने तथा उनमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

#### घरेलू उद्योग

5) निर्णायक समीक्षा हेतु आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मेसर्स कल्याणी लेमरेज लिमिटेड, पुणे और मेसर्स व्हील्स इण्डिया लिमिटेड चेन्नै ने प्रस्तुत किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन में आवेदकों का प्रमुख हिस्सा है और इसलिए वह नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

#### निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

6) मूल जाँच और वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "वाणिज्यिक वाहनों के ट्यूब टायर अनुप्रयोग में प्रयुक्त 16" नॉमिनल व्यास से 20" नॉमिनल व्यास वाले फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" (सम्बद्ध वस्तुएं) हैं। वर्तमान जाँच निर्णायक समीक्षा जाँच होने के कारण इस जाँच में मूल जाँच में शामिल उत्पाद शामिल है।

7) फ्लैट बेस स्टील व्हील्स रिम और डिस्क का संयोजन है जो एक डिमाउंटेबल रिंग के साथ जुड़ा होता है। रिम और डिस्क का उत्पादन अलग-अलग संयंत्रों में किया जाता है और उनकी वेल्डिंग करके उन्हें व्हील

का रूप दिया जाता है, जिन्हें वाहन को चलाने के लिए वाहन के एक्सल में माऊंट करके टायरों से जोड़ दिया जाता है। वाणिज्यिक वाहनों में बसें, ट्रक सहित लॉरियां, टैरिफ, टेम्पो आदि शामिल हैं। व्हील्स को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 87 के अन्तर्गत उपशीर्ष 870.70 के तहत "रेलवे अथवा ट्रामवे रोलिंग स्टॉक को छोड़कर अन्य वाहन और उनके पुर्जे तथा उप साधन" के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

### **निर्णायक समीक्षा की शुरुआत**

8) यतः विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए किए गए आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसरण में प्राधिकारी सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों के अधिरोपण को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जाँच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त करने की परिणति पाटन व क्षति के जारी रखने अथवा उसकी पुनरावृत्ति में होगी, एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं।

### **शामिल देश**

9) जाँच में शामिल देश चीन जन गण है।

10) वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1 अप्रैल 2010 से 30 सितम्बर, 2011 (18माह) है। तथापि क्षति के विश्लेषण में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और जाँच अवधि को शामिल किया जाएगा।

### **प्रक्रिया**

11) वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 28 नवम्बर 2007 को अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं।

12) इस समीक्षा पर उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19, और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

### **सूचना प्रस्तुत करना :**

13) संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संगत प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से सभी सूचना प्रस्तुत करने तथा निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**कमरा नं. 240, उद्योग भवन**  
**नई दिल्ली-110107**

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**समय-सीमा :**

15. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जाना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौजूदा मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना देने तथा प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने और जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना :**

17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ सं. इत्यादि सहित) तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ सं. इत्यादि सहित)। प्रस्तुत की गई प्रत्येक सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” चिह्नित होना अनिवार्य है।

18. गोपनीय के चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को आगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का अवलोकन करने की अनुमति देने का अधिकार होगा। गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों रूपांतरों की दो-दो प्रतियाँ आवश्यक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

19. जिस सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया हो; उस सूचना के प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सूचना के साथ समुचित कारणों सहित इस आशय का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है तथा/अथवा ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

20. अगोपनीय सूचना का गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, गोपनीय सूचना को सूचीबद्ध किया जाए या रिक्त छोड़ दिया जाए/संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है; कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

21. प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच पर गोपनीयता हेतु निवेदन को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु निवेदन प्राधिकृत नहीं है अथवा सूचना प्रदायक या तो सूचना सार्वजनिक करने या सामान्य अथवा संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक हो तो वे इस तरह की सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय रूपान्तर के बिना अथवा गोपनीयता माँग के लिए उचित कारण ब्यौरा दिए बिना किसी तरह का निवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट होने की स्थिति में तथा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करते हुए, इस तरह की सूचना प्रदान करने वाली पार्टी के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इसे किसी पार्टी के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपान्तर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

### असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

59440112-2

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2012

**Initiation (Sunset Review)****Subject : Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of Flat Base Steel Wheels, originating in or exported from China PR.**

**F. No. 15/22/2011-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of "Flat Base Steel Wheels of size 16" nominal diameter to 20" nominal diameter used in tubed tyre application in commercial vehicles" (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

1) WHEREAS, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/8/2005-DGAD dated 21st May 2006. The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification No. 14/8/2005-DGAD dated 12th January 2007 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 51/2007 Customs dated 29th March, 2007. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No. 14/8/2005-DGAD dated 28th November 2007, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed w.e.f 29th March, 2007 by the Department of Revenue vide Notifications No. 124/2007-Customs dated 31st December, 2007 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

2) Whereas, some of the interested parties had filed appeals before CESTAT against the Final Findings of the Authority. The Hon'ble CESTAT vide its order dated 11th August, 2011 remanded the matter back to the Designated Authority for affording post-decisional hearing to the appellants and for making such modifications to the Final Findings as may be necessary as a result of such post decisional hearing.

3) Whereas, in compliance with the orders of the Hon'ble CESTAT and without prejudice to the rights of the Designated Authority to challenge the orders on the matters of law and principle, the Authority held a post decisional oral hearing for the known interested parties on 13th December 2011 and issued the post decisional findings vide Notification No. 14/8/2005-DGAD dated 10th February, 2012, re-affirming its final findings made vide earlier Notification No. 14/8/2005-DGAD dated 28th November 2007 and the recommendations made therein.

4) Whereas, M/s. Kalyani Lemmerz Limited, Pune and M/s Wheels India Limited, Chennai have filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the producers of the subject goods in India, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

#### **Domestic Industry**

5) The application for the sunset review has been filed by M/s. Kalyani Lemmerz Limited, Pune and M/s Wheels India Limited, Chennai, on behalf of the domestic industry. As per the information available, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

#### **Product under consideration and Like Article**

6) The product under consideration, in the original as well as the present sunset review investigation, is "Flat Base Steel Wheels of size 16" nominal diameter to 20" nominal diameter used in tubed tyre application in commercial vehicles" (the subject goods), originating in or exported from China PR. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product covered in the original investigation.

7) Flat base steel wheels are assembly of rim and disc with a demountable ring. Rims and discs are produced in separate lines and welded together to form a wheel, which is mounted on the axles of vehicles and fitted with tyres to enable vehicle movement. Commercial vehicles comprise of buses, lorries including trucks, trailers, tempos, etc. Wheels are classified under Chapter 87 of the Customs Tariff Act under the category of "vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof" under the sub-heading 8708.70. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

#### **Initiation of Sunset Review**

8) WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

#### **Country involved**

9) The country involved in this investigation is China PR.

#### **Period of Investigation**

10) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1<sup>st</sup> April, 2010 to 30<sup>th</sup> September, 2011 (18 months). However, injury analysis shall cover the years 2007-08, 2008-09, 2009-10 and the POI.

594 96712-3

**Procedure**

11) The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No.14/8/2005-DGAD dated 28<sup>th</sup> November 2007

12) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**Submission of Information**

13) The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Ministry of Commerce and Industry  
Department of Commerce  
Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.**

14) Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limit**

15) Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

16) All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**Submission of information on confidential basis**

17) In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.



18) Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

19) For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20) The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

21) The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22) Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of public file:**

23) In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

24) In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority